web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 05 अगस्त 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 306

महत्वपूर्ण एवं खास

चीन के हेनान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 302 हुई

बीजिंग। चीन के हेनान प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार तक बढ़कर 302 हो गई है। स्थानीय सरकार के सूचना कार्यालय ने यह जानकारी दी है। अन्य 50 लोग लापता हैं। प्रांतीय राजधानी झेंग्झौ में कुल 292 लोगों के मारे जाने और 47 के लापता होने की पुष्टि हुई है। शिनजियांग शहर में सात लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हो गए, जबकि पिंगडिंगशान और लुओहे ने क्रमशः दो और एक की मौत की सूचना दी।

चंबल पर बना पुराना पुल डूबा

धौलपुर (आरएनएस)। राजस्थान में चंबल नदी के खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बहने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीन पर बना पुराना पुल पानी में डूब गया है। मानसून की अच्छी बरसात में चंबल नदी में पानी आवक बढ़ने से उसके किनारे बसे 14 गांव भी जलमग्न गये हैं। कोटा बैराज से पानी की निकासी के बाद चम्बल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। चम्बल का गेज खतरे के निशान 130 79 के स्थान पर 143 मीटर पर पहुंच गया है। चम्बल नदी पर स्थित पुराना सड़क पुल भी डूब गया है। दर्जनभर गांवों का सम्पर्क कट गया है वहीं चंबल किनारे स्थित श्मशान घाट के अंदर पानी आ गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर रखे है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने 29 मंत्रियों वाले कैबिनेट की घोषणा की, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 29 मंत्रियों वाले कैबिनेट की घोषणा की है, जिसमें कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। बोम्मई को पिछले हफ्ते बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और 28 जुलाई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस युदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को शामिल नहीं किया गया है। कैबिनेट में 8 लिंगायत, वोक्कालिंगा और ओबीसी से 7-7 मंत्री, 3 दलित, 1 एसटी और एक महिला को मंत्री बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के कुछ हिस्सों में बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की गम्भीरता को कम करने में मदद के लिए केंद्र से हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया। पीएम ने स्थिति की गम्भीरता को कम करने में मदद के लिए केंद्र से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमन्त्री मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना की है।

काबुल में रक्षा प्रतिष्ठानों के पास हुआ विस्फोट

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को रक्षा प्रतिष्ठानों के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम दो लोग घायल हो गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता फिरदौस फरमार्ज ने एक लिखित संदेश के माध्यम से संवाददाताओं को बताया कि पुलिस जिला 10 में (स्थानीय समयानुसार) सुबह 8.15 बजे एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण में विस्फोट किया गया, जिसमें दो लोग घायल हो गये। धमाका काबुल हवाईअड्डे के पास स्थित एक इलाके में हुआ जहां कई अपार्टमेंट और इमारतें स्थित हैं। इस बीच, अनौपचारिक सूत्रों ने बताया कि घायलों में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी भी शामिल है। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि काबुल पिछले कुछ वर्षों में सरकार का विरोध करने वाले तालिबानी आतंकवादियों और इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों के सिलसिलेवार हमलों से प्रभावित रहा है।

कैबिनेट ने फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये) की धनराशि निर्धारित की गयी है। केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी। यह योजना 02 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया है। बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने पहले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। बारह वर्ष से

कम उम्र की नाबालिग लड़कियों और सोलह वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस तरह की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के परीक्षण के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता थी, जो मुकदमे में तेजी ला सके और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके।

ऐसे मामलों में अधिक कड़े प्रावधान, त्वरित सुनवाई और मामलों के निपटान के लिए, केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया और दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया। इससे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना हुई।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय समर्पित अदालतें हैं, जिनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है। इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है।

वर्तमान में ये न्यायालय 28 राज्यों में कार्यरत हैं और सभी 31 राज्यों, जो योजना में शामिल होने के पात्र हैं, में इनके विस्तार का प्रस्ताव है। यह देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

24 घंटों में 42,625 नए मामले, 562 मरीजों की मौत

» देश में कोरोना ने फिर पसारे पैर

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के मामले में दो दिन से गिरावट के बाद आज फिर से अपने पैर पसार लिये हैं। पिछले 24 घंटे में 42,625 नए संक्रमितों के सामने आने के बाद कोरोना महामारी में बड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं इस दौरान संक्रमण के कारण हुई मौतों में भी उछाल के साथ 562 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के बढ़ने से सक्रीय मामलों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है यानि बीते एक दिन में करीब 9 हजार सक्रीय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के बीते एक दिन में 42,625 नए मामले एक दिन मंगलवार हो दर्ज 30,549 नए मामले के मुकाबले 12 हजार से भी ज्यादा हैं। हालांकि इन नए मामलों में आधे से ज्यादा केरल के हैं, जहां एक बार फिर से रिकॉर्ड 23 हजार 676 केस दर्ज किए गए हैं। यानि सबसे ज्यादा चिंता केरल को लेकर है, जहां पिछले तीन दिन में दोगुना से भी ज्यादा मामले दर्ज किये गये।

तीन करोड़ से ज्यादा ने दी कोरोना को मात- आंकड़ो के अनुसार मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,668 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी तक देश में कोरोना से कुल 3 करोड़ 9 लाख 33 हजार 22 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में मौजूदा रिकवरी रेट 97.37 फीसदी है। फिलहाल देश में कोरोना के 4,10,353 इलाजरत सक्रीय मरीज हैं, जो कि देश में आए संक्रमण के कुल मामलों का 1.29 फीसदी है।

उपराष्ट्रपति ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की बात की

नई दिल्ली (आरएनएस)। नायडू ने ये बातें तब कही जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी उनसे उपराष्ट्रपति निवासमें मुलाकात कर रही थीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

मंत्री द्वारा उन्हें हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई।

मती इरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हाल ही में किए गए संशोधन में जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने और अनाथ बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें राज्यों की साझेदारी से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन एवं पुनर्वास उपायभी शामिल हैं।

नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों प्रति उनके मन में एक नरम भाव है और उन्होंने दोहराया कि अनाथ बच्चों केकल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सरकार और समाज की है। हाल ही में, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उनसे उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात किया।

वैवाहिक विवाद में बच्चे के डीएनए टेस्ट को नहीं दी जा सकती अनुमति : सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एडल्ट्री (व्याभिचार) का कोई प्राथमिक सबूत नहीं है तो शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने निचली अदालत और बोम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद में

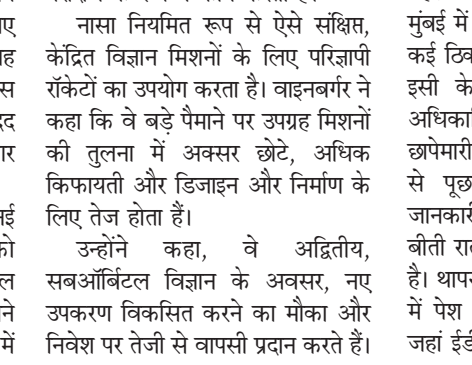

अपने बच्चे के डीएनए टेस्ट का आदेश देने की याचिका की अनुमति दी थी, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि वह उस बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है और उसकी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध थे।

भारतीय एविडेंस अधिनियम की धारा 112 का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि एडल्ट्री (व्याभिचार) साबित करने के लिए सीधे डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता है और निचली अदालत और हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने में गलती की है।

बता दें कि ये धारा एक बच्चे की वैधता के अनुमान के बारे में बताती है। पीठ ने कहा कि एडल्ट्री के आरोप को साबित करने के लिए कुछ प्राथमिक सबूत होने चाहिए और उसके बाद ही अदालत डीएनए टेस्ट पर विचार कर सकती है।

याचिका देने वाले इस कपल की शादी 2008 में हुई थी और 2011 में इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। जिसके छह साल बाद पति ने तलाक की याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्होंने बच्चे के डीएनए टेस्ट के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि निचली अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया।

नासा ने सोलर कोरोना का पता लगाने के लिए सोलर एक्स-रे इमेजर किया लॉन्च

वाशिंगटन। नासा के वैज्ञानिकों ने सब-ऑर्बिटल उड़ान पर साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से एक परिष्कृत एक्स-रे सोलर इमेजर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है कि कैसे और सूर्य का कोरोना पृथ्वी के मूल तारे की वास्तविक सतह की तुलना में इतना गर्म क्यों होता है। अलबामा के हंट्सविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के डेवलपर्स, मिशन को मैगिक्स कहते हैं - मार्शल ग्राज़िंग इंसीडेंस एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इसे दोपहर 2.20 बजे न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया।

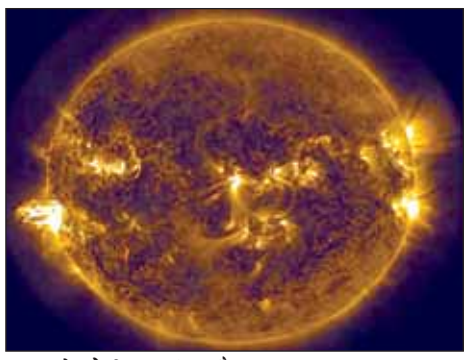

मैगिक्स मिशन ने अपने पेलोड को भेजा, जिसमें एक बड़े शक्ति वाला कैमरा, टेलीस्कोप और एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है।

मैगिक्स के प्रमुख अन्वेषक मार्शल हेलियोफिजिसिस्ट एमी वाइनबर्गर ने कहा, कोरोना के ताप तंत्र के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है, आंशिक रूप से क्योंकि हम अभी तक इस क्षेत्र में सौर प्लाज्मा के तापमान वितरण का विस्तृत अवलोकन और माप नहीं कर पाए हैं। सूर्य की सतह का तापमान 10,000 डिग्री फारेनहाइट से अधिक है, लेकिन कोरोना नियमित रूप से 1.8 मिलियन डिग्री फारेनहाइट से अधिक मापता है।

एक सक्रिय सौर क्षेत्र के विभिन्न भागों में विशिष्ट तापमान वितरण को मापने के लिए मैगिक्स पहला इमेजर होगा। वह सटीक डेटा वैज्ञानिकों को इस बहस को सुलझाने में मदद करेगा कि कोरोना कैसे और कितनी बार सुपर हीट होगा है।

कोरोनल हीटिंग मैकेनिज्म पर नई रोशनी डालने से शोधकताओं को संभावित सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को बेहतर ढंग से समझने और यहां तक कि भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकता है, जो दोनों कोरोनल हीटिंग में क्षेत्रीय स्पाइक्स के संबंध में सबसे अधिक बार होता हैं।

मैगिक्स साउंडिंग रॉकेट मिशन भविष्य के नासा मिशनों के लिए अधिक विस्तार से सौर फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक परीक्षण के रूप में कार्य करता है।

नासा नियमित रूप से ऐसे संक्षिप्त, केंद्रित विज्ञान मिशनों के लिए परिज्ञापी रॉकेटों का उपयोग करता है। वाइनबर्गर ने कहा कि वे बड़े पैमाने पर उपग्रह मिशनों की तुलना में अक्सर छोटे, अधिक किफायती और डिजाइन और निर्माण के लिए तेज होता हैं।

उन्होंने कहा, वे अद्वितीय, सबऑर्बिटल विज्ञान के अवसर, नए उपकरण विकसित करने का मौका और निवेश पर तेजी से वापसी प्रदान करते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मंगलवार को बिजनैसमैन और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसियों ने दिल्ली और मुंबई में अवंता ग्रुप और थापर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी के साथ कई और वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। इसके बाद थापर से पूछताछ भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक थापर को बीती रात को गिरफ्तार किया गया है। थापर को बुधवार को अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगा। अधिकारियों के अनुसार ईडी थापर की कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस साल जून में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने थापर समेत उनके दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित दो निजी फर्मों के प्रमोटरों और निदेशकों को यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया था।

राष्ट्रपति ने विलिंगटन के 77वें स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को किया संबोधित

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, विलिंगटन के 77वें स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को संबोधित किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के सशस्त्र बल हमारे महान राष्ट्र के सर्वाधिक सम्मानित संस्थाओं में शामिल हैं। अपने अथक प्रयासों तथा महान बलिदानों के बल पर इन्होंने देशवासियों से सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने युद्ध एवं शांति के समय राष्ट्र को अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ प्राकृतिक

आपदाओं के समय भी उन्होंने समर्पण एवं साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है।

कोविड-19 महामारी के बारे में चर्चा करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हाल में बीता हुआ समय पूरी मानवता के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा है। इस महामारी ने जीवन के सभी हिस्सों को प्रभावित किया है। कोविंद ने देश की सीमाओं के साथ-साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में सशस्त्र बलों के पुरुषों एवं महिलाओं के बेजोड़ साहस एवं संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में इनमें से अधिकांश व्यक्ति अग्रणी योद्धाओं में शामिल हैं। देश उनकी प्रतिबद्धता तथा उनके योगदान की सराहना करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जो बदलावों से भरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा की अवधारणाएं बदल रही हैं। भू-रणनीतिक एवं भू-राजनैतिक बाध्यताओं के साथ-साथ अन्य घटकों ने सुरक्षा परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है। कम तीक्ष्णता के संघर्ष, आतंकवाद से मुकाबला और गैर-युद्धक संघर्ष विभिन्न चुनौतियां पेश करते हैं। सभी पहलुओं को गहराई से समझने की जरूरत है। इस बदलते समय में हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ कोर्स के दौरान छात्र अधिकारियों को बदलती गतिशीलता को समझने में मदद करने के लिए व्यापक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वृहद परिदृश्य की समझ के साथ वे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में अपनी भूमिका की पहचान करने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी के समाज को ज्ञान आधारित समाज के रूप में वर्णित किया गया है। सचमुच, इस सदी में ज्ञान एक शक्ति है। जिस तरह हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के युग में होना बताया जाता है, वैसे ही हम ज्ञान आधारित युद्ध के युग में भी हैं। रक्षा पेशेवरों के रूप में, अधिकारियों को एक ज्ञान आधारित योद्धा होना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पेशेवर शिक्षण के बल पर वे आवश्यक दक्षताओं को आत्मसात करने में सक्षम होंगे। यह उन्हें भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सही उपायों से लैस करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के प्रभावकारी अगुआई के लिए, अधिकारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करनी होगी। आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, नम्रता एवं सरलता उन्हें एक व्यक्ति के रूप में सशक्त करेंगे। अत्याधुनिक तकनीकों, अत्याधुनिक रणनीतियों तथा युक्तियों और नवीनतम खोजों के निरंतर शिक्षण से वे अच्छे पेशेवर बनेंगे।